



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1973/अग्रहायण 21, 1895

No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 1973/AGRAHAYANA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रत्येक संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th December 1973

S.O. 780(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 748(E)/18FB/IDRA/72, dated the 14th December, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to Banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as M/s. Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur (Spinning Unit) or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year.

[No. F.11021/11/4/72-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1973

का० आ० 780 (अ).—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 746 (ई) 18 एफ बी० /आई डी आर ए/ 72, तारीख 14 दिसम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित से भिन्न) सभी संधिदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापकों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का प्रवर्तन, जिनका मेमर्स एसो-सीयटेड इंडस्ट्रीज (आसाम) लि०, चन्द्रपुर (स्प्रिंग यूनित) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की अवधि के लिए, निलंबित रहेगा, और उक्त तारीख के पूर्व तब्दीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए, निलंबित रहेंगे, और यतः केन्द्रीय सरकार का वह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए, और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त आदेश की अवधि को एक और वर्ष के लिए, बढ़ाती है।

[सं० फा० 11021/114/72-एन टी सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।